

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक:-...../

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-०३/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से ए०एम०जी०/एम०एम०जी० के तहत लंबित विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र सब्सिडी राशि की व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के प्रभावी तिथि से ए०एम०जी०/एम०एम०जी० के तहत लंबित विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹500.00 लाख (पाँच करोड़) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का व्यय उद्योग विभागीय संकल्प सं०-691, दिनांक-09.06.2011 द्वारा घोषित प्रावधानों/दिशा निदेश के अनुरूप किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80- सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य योजना आय-व्ययक में बजट उपबंध एवं उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों को औद्योगिक नीति के प्रभावी तिथि से AMG/MMG के तहत विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा 7 (सात) वर्षों के लिए मान्य है।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना से विद्युत संबंधी छूट/प्रतिपूर्ति हेतु उद्यमियों को दी गई वास्तविक छुट की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त दावा के विरुद्ध राशि का भुगतान बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०, पटना को सी०एफ०एम०एस० प्रावधान के माध्यम से उनके बैंक खाता में उपलब्ध करायेगें।

6. योजना के नियंत्रण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेगा।

7. यह राज्य सरकार की चालू योजना है। राशि की निकासी फार्म बी०टी०सी०-25 पर की जायेगी।

8. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्ब्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।

9. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन सं० सं०-०३/उ०नि०/योजना (औ०प्रो०नीति)-०२/२०१५ के पृष्ठ 220/टि० पर प्राप्त है।

क्रमशः पृष्ठ-02...

10. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं० सं०-03/उ०नि०/योजना (औ०प्रो०नीति)-02/2015 के पृष्ठ-233/टि० पर दिनांक-31.07.2019 को प्राप्त हैं।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-2561 दिनांक-17.06.98 की कड़िका-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8244 दिनांक-02.08.2010 के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि०(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015

प्रतिलिपि:-सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-1.8.19.....

ज्ञापांक:- 3021...../

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) क० लि०, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक (तक०), तकनीकी विकास निदेशालय/उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी-1, उद्योग विभाग/प्रशाखा-2 (उ०नि०), उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, एस०आई०पी०बी० एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

1.8.19